



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 1990/भाद्र 2, 1912

No. 477]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 1990/BHADRA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990

का.आ. 655(अ) :— यह: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मामला सं. भा.र.सी.
2/84-एस.प्रा.र.मू. III/एस.प्रा.र.सी./सी.बी.प्रा.इ., दिनांक 14 जून, 1984 (गोल्डन
ट्रिप्पल केस) में अभियुक्त के विलाप मामलों को बारम्बास ले लिया है;

यह: जालंधर, पटिकला तथा फिरोज़पुर के नवायिह जोनों के संबंध में अतिरिक्त विवेद
स्थायीकरण, जोरपुर में कोर्ट आवाये पैदित भवी है;

2287 GI/99 (1) गोल्डन ट्रिप्पल केस, भारत सरकार के विलाप मामलों को बारम्बास ले लिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी झेट (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा 15-के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के मृह संवादप को अधिसूचना संस्था सा.का.नि. 803 (श्र.), दिनांक 28 जुलाई, 1984 के तहत यथा स्थापित जालंधर न्यायिक जोनों से संबंधित आंतरिक विशेष न्यायालय को 31 अगस्त, 1990 से समाप्त करनी है।

[S. 1/3/90-लीगल सेल]
ग्राहक भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 1990

S.O. 655(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Home Affairs withdrew the cases against the accused in case No. RC. 2[84-SIU. III] SIC|CBI dated the 14th June, 1984 (Golden Temple Case);

Whereas no work is pending in the Additional Special Court, Jodhpur in relation to judicial zones of Jullunder, Patiala and Ferozpur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, the Central Government hereby abolishes with effect from the 31st August, 1990, the Additional Special Court in relation to judicial zones of Jullunder, Patiala and Ferozpur as established under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 803(E) dated the 4th December, 1984.

[No. 1/3/90-Legal Cell]
ASHOK BHATIA, Jr. Secy.